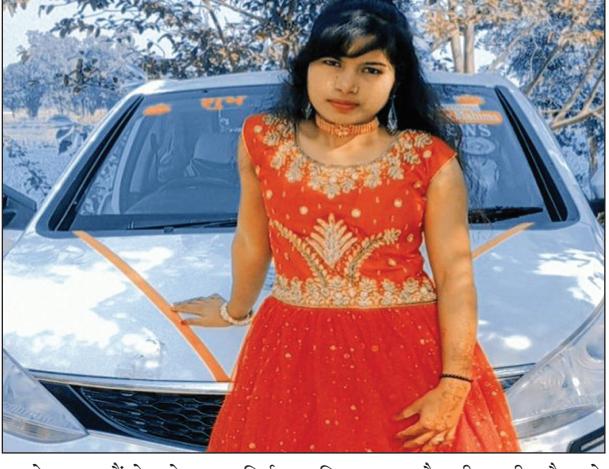


सीटी आस-पास संदेश

सोरों कटरा बाजार में फार्म ऑनलाइन कराने गई युवती का थरवई में मिला शव

अखंड भारत संदेश



जंघई। सरायमरेज थानांतर्गत सिंधोरा, सोरों गांव निवासी भानु प्रताप सिंह की बेटी रेतु सिंह उम्र 21 वर्ष शुक्रवार को सुबह 11 बजे के करीब गांव के पास साहबर कैफे में फार्म ऑनलाइन करवाने गई थी, लेकिन वापस रहने नहीं लौटी जिससे परिजन हैंगां परेशन है। योजनावान करने पर भी जानकारी नहीं हुई। रात में जीआरपी पुलिस थरवई ने भानु प्रताप सिंह को सूचना दिया कि थरवई थाना क्षेत्र के कनेहीरी रेले कांसिंग के बाल मृत युवती का पैर कटा शव मिला है, जिस पर भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे तो उनकी बेटी रेतु सिंह ही थी। भानु सिंह ने बताया कि बेटी घर से विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन फार्म भरने कटरा सोरों गई थी लेकिन उसका अपहरण करके

प्रतापगढ़ संदेश

सीबीएसई की इंटर गणित की परीक्षा में 2500 परीक्षार्थी हुए शामिल

जिले के सात केन्द्रों पर सम्पन्न हुई परीक्षा

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़ सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की गणित विषय की परीक्षा शनिवार को जिले के सात परीक्षा केन्द्रों क्रमशः न्यू एंजिल्स सी से स्कूल, संगम इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल, संगम इंटरनेशनल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आईएसई परिक्षा स्कूल लालांगंज और पहिंत नारोग दत्त परिक्षा स्कूल में हुई। इस परीक्षा में प्रतापगढ़ के 37 सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लगभग 2500 परीक्षार्थी शामिल हुए। न्यू एंजिल्स सीनियर सेकेन्डरी



न्यू एंजिल्स स्कूल से परीक्षा देकर बाहर निकलते परीक्षार्थी।

स्कूल की चेतावनपूर्ण टाइम 10 शाहिदा व सीबीएसई के स्टीरी कोऑफिनेंटर तथा न्यू एंजिल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के प्रिसिपल विधिन कुमार सोनी ने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सकुशल संप्रभु हुई।

हाईस्कूल उर्दू में 961 छात्रों ने दी परीक्षा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल उर्दू, युजरती, मराठी, काशमीरी की परीक्षा में 961 छात्रों ने परीक्षा दी जबकि 101 छात्र अनुपस्थित हो गये। इसी प्रकार इंटर मीडिएट व्यासांगिक में 560 बच्चों ने परीक्षा दी। जबकि 18 अनुपस्थित हो गये। शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न हुई। कहीं किसी भी परीक्षा में कोई अधिक घटना नहीं सामने आई।

आज के पेपर को मॉडेट तथा कुछ ने लंबा बताया। परीक्षार्थियों के अनुसार, कुल 38 सवाल थे। जिसमें कुल 3 सवाल तथा 2 व्याकिलीय सवालों का था।

इसमें कुल 18 सवाल तथा 2 व्याकिलीय सवालों का था। शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न हुई। कहीं किसी भी परीक्षा में कोई अधिक घटना नहीं सामने आई।

आज के पेपर को मॉडेट तथा कुछ ने लंबा बताया। परीक्षार्थियों के अनुसार, कुल 38 सवाल थे। यह सेक्षेन कुल 10 अंकों के लिए पूछे गए थे। यह सेक्षेन कुल 10 अंकों के लिए पूछे गए थे। न्यू एंजिल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल की चेतावन परसन डॉक्टर शाहिदा ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल के समाप्त होगी। सीबीएसई कक्षा 12वीं की अग्रिम परीक्षा फिजिकल एजुकेशन की 12 मार्च को होगी।

तेलुगु उत्तरीय के 5 सवाल प्रत्येक

पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों की हो रही कटाई

अखंड भारत संदेश

पट्टी, प्रतापगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेवादा गांव में पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों की धड़िल्ले से कटाई की जा रही है। बता दें कि वन माफिया आए दिन क्षेत्र में दिनदहाड़े हो एवं प्रतिवर्षित पेड़ काट रहे हैं। यह सब गोलमाल पुलिस हुआ वन विभाग की मिलीभगत से क्षेत्र में संचालित हो रहा है। पट्टी तहसील क्षेत्र के कैरला, इटरा मुजाही, खदवानांज, उड़ैयाडी, सोनही सहित आदि जाहों पर वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से अवैध धारा मशीन का संचालन हो रहा है। इन आरा मशीन संचालक द्वारा हरे भेरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इस पर ना तो वन विभाग कर्मी



हरे पेड़ों की कटाई करते लोग।

का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ऐसे अवैध आरा मशीन संचालक के खिलाफ करवाई करने की मांग की है। वन विभाग के रेंज पट्टी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल नाट रीवेल बता रहा था।

शिवाला महोत्सव में आकर्षक प्रस्तुतियों पर मंत्रमुग्ध हुए लोग

पूर्व विधायक ने की शिरकत, बच्चों ने प्रस्तुत किये सांस्कृतिक कार्यक्रम

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। नगर क्षेत्र के पूरे ईश्वरनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर पर आयोजित दो दिवसीय छठवें शिवाला महोत्सव के शुभारंभ के दूसरे सत्र सांकाकाल नेहल युवा केन्द्र के कलाकारों व आनन्द इण्टर कालेज के बच्चों द्वारा विषय सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहाँ जांकी का कार्यक्रम देख पूरा पूरा माहाल भक्ति से सराबोर हो गया।

राधा-कृष्ण व कृष्ण-सुदामा की जांकी प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने कहा कि शिवाला महोत्सव में सभी के सहयोग से आकर्षक

शिवाला महोत्सव में मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार पाल व अन्य।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य भव्य सहयोग रहा। इस मौजैके पर आशीर्वाद देश को विकास की गति मिलती है। ऐसे कार्यक्रम में प्रत्येक लोगों को बढ़-चढ़कर सहभागिता

शिवाला महोत्सव में मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार पाल व अन्य।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा। इस मौजैके पर आशीर्वाद देश को विकास की गति मिलती है। ऐसे कार्यक्रम में प्रत्येक लोगों को बढ़-चढ़कर सहभागिता

शिवाला महोत्सव में मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार पाल व अन्य।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्रदीप शुभल, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौजैके पर राधाकृष्ण वैशिक महासंघ के राजेश प्रशान्त ने कहा कि इसे कार्यक्रमों के द्वारा योग्य सहयोग रहा।

शुभल एवं प्र

संपादक की कलम से

अबकी बार, बहानों की बयार

भाजपा शासन में 2018 में लाई गई चुनावी बॉड योजना पर शुरूआता से से सवाल उठे, इसे रिश्वतखेत्री का नया तरीका बताया गया, लेकिन भाजपा के पहले कार्यकाल में लायी गई यह योजना दूसरे कार्यकाल में बेधिक चलती रही। इस पर कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गईं और चुनावों में धन के खर्च और पारदर्शिता का हवाला दिया गया। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने 15 फरवरी को चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये स्विधान के तहत सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के काम में संलग्न एकमात्र बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अदालत ने निर्देश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने पेश करे। इस आदेश का मकसद यह था कि आने वाले आम चुनावों के पहले जनता को यह पता चले कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा अब तक मिला है और किन लोगों या किन कारोबारी घरानों ने कितने की रकम चुनावी बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश को खास तौर पर भाजपा के लिए बड़े झटका माना गया था, क्योंकि देश में इस वक्त सबसे अधिक धन भाजपा के ही पास है। सत्तारुद्ध दल होने के कारण चंदे की रकम भी उसे ही सबसे ज्यादा मिली होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन चुनावी बॉन्ड के दो दोषों के बारे में विवाद हो रहा है।

बाड म गोपनयता क नियम के कारण अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया था कि भाजपा को किन लोगों से कितना धन मिला और इस चंदे के एवज्ज में सरकार से उन लोगों को कोई विशेष लाभ दिया गया या नहीं। भाजपा सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड पर जो अधिसूचना जारी की थी, उसके कलांज 7 (4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हैं सूरत में इलेक्ट्रोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखे। सरकार का कहना था कि इस तरह चंदा देने वाले को राजनैतिक दलों के प्रतिशोध से बचाया जा सकेगा। यानी यह पहले ही मान लिया गया था कि किसी

राजनैतिक दल की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कोई चंदा नहीं देगा, बल्कि चंदे के बदले फायदा हासिल करने के लिए दिया जाएगा। बहरहाल, शीर्ष अदालत के आदेश के बाद यह माना जा रहा था कि अब चुनाव से पहले ही चुनावी बॉन्ड खरीदारों की जानकारी सामने आ जाएगी और इस पर भाजपा ने चुनाव में पारदर्शिता या ईमानदारी के जितने र्थं तर्क दिए हैं, उनकी परख भी हो जाएगी। लेकिन एसबीआई ने छह तारीख लाइसेंस की समय सीमा पूरी होने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर कहा है कि चुनावी बॉन्ड के मामले में जानकारी देने के लिए 30

जून तक का वक्त दिया जाए। अर्जी में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं। यह बॉन्ड अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए जारी हुए हैं। बैंक का यह भी कहना है कि देश की अलग-अलग शाखाओं में बॉन्ड खरीदे और भुगाए गए हैं। खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या, इन सबका आंकड़ा किसी सेंट्रल सिस्टम में नहीं है। गोपनीयता के कारण बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को भासने से

के कारण बांड जारी करने से सजावता डॉ जा. बांड का तुलना स्वरूप संबंधित डेटा दोनों को दो अलग-अलग जगहों में रखा गया, इसका कोइसे संट्रल डेटाबेस नहीं रखा गया और अब ये सब मुंबई में बैंक की मुख्य शाखा में एक साथ स्टोर किया गया है। बॉन्ड खरीद और भुगताने के डिटॉल के दो अलग-अलग सेट हैं, यानी 22 हजार 217 बॉन्ड की जानकारी के लिए 44,434 सेट डिकोड करने होंगे, फिर उन्हें आपस में मिलाना होगा, उनकी तुलना करनी होगी और तब जाकर पता चलेगा कि किसने किस दल को कितने का चंदा बॉन्ड खरीद कर दिया है। गोपनीयता के

नियम का हवाला देते हुए एसबीआई ने जो दलील अपने आवेदन में पेश की है, उसे देखकर एकबारगी यही लगेगा कि वार्कइंग इस काम में कार्फेर वक्त लगेगा। लेकिन डिजीटल इंडिया के इस दौर में यह बहानेबाजी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। मान लिया कि बैंक ने बॉन्ड्स खरीदने वालों की जानकारी गोपनीयता के कारण सेंट्रल सिस्टम में नहीं चढ़ाई, लेकिन कहीं तो ये डेटा दर्ज है ही और और अपने ही सिस्टम में दर्ज डेटा निकालने के लिए बैंक को चार महीने का वक्त क्यों चाहिए।

बेईमान रवैया

बनने के लिए तैयार हो चुका है। सरकारी, गैर-सरकारी संस्थानों में महिलाओं का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम किए होंगे। पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होंगे, जिनमें भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिए जाने की महान परंपरा की बातें होंगी। 21वीं सदी में देश में सेना, विज्ञान शिक्षा, खेल-कूद, कारोबार, कला-संस्कृति हर क्षेत्र में महिलाओं ने कितनी उन्नति की है, इसके उदाहरण पेश किए जाएंगे। महिला राष्ट्र परिषद् से लेकर विभिन्न किस्म के उच्च पदों पर बेटी महिलाओं की जीवनगाथाएँ प्रस्तुत होंगी। हर साल यही सब होता आया है और आगे भी होता रहेगा। स्त्री शक्ति को रेखांकित करते ऐसे आयोजनों में पीड़ित, शोषित और वंचित महिलाओं की बातें बड़े सुविधाजनक तरीके से किनारे कर दर्द जाती हैं। मौजूदा सरकार का भी यही तरीका है। अब 2014 वाला दौरा नहीं रहा, जब निर्भया कांड के बाद सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने के लिए जनता अगर सड़कों पर उतर आई तो तत्कालीन सरकार ने ऐसा करने से जनता को नहीं रोका, न ही इस मामले को दबाने के लिए कोशिश की या इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा किए जाने के कार्यकाल में एक जघन्य अपराध घटित हुआ है। बल्कि तब कांग्रेस सरकार ने निर्भया के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाई, पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवार को राहुल गांधी ने सहारा दिया, उनके खाइ को पायलट बनाने में मदद की, लेकिन कभी इस का कोई प्रचार नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बरसों-बरस मनाने और लैंगिक समानता का ढोल पीटने के बावजूद यह एक कड़वी हकीकत है कि महिलाओं के लिए बराबरी और सम्मान की सोच समाज में अब तक व्याप्त नहीं हो पाई है। किस्म-किस्म के भेदभाव और अत्याचार महिलाओं पर होते रहे हैं और इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका व्यापक संबंध समाज की मानसिकता से जुड़ा है। सरकारें अपने फैसलों और नीतियों से इस मानसिकता को सुधारने का काम अवश्य कर सकते हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण जैसे विस्तृत विषय को राजनीति से दूर रख सकती हैं। खेद है कि मौजूदा केंद्र सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है और बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं जैसे एकाध नारे और दो-चार योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री नारी सशक्तीकरण का श्रेय लेना चाहते हैं। नये संसद भवन में महिला आरक्षण पर विधेयक पारित करवा कर उन्होंने इतिहास रचने का दावा भी किया, हालांकि उनके दावों की हकीकत कई बार जनता देख चुकी है। महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर उनका दुविचापन भी अब सामने आ चुका है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोर्दं प.बंगल में थे, जहां हाल ही में उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली तथा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख पर लगा है। शाहजहां शेख फिलहाल कानून की गिरफ्त में है। प.बंगल में भाजपा इस बार लोकसभा नाव में तृणमूल कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में भाजपा की नारी शक्ति अधिनंदन रैली की और इसमें कहा कि संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से छुक जाएगा। लेकिन टीएमसी सरकार अपराधी को बचाने पर तुली हुए हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके दस साल के शासनकाल में महिलाएं कितनी मजबूत हुई हैं। श्री मोदी ने संदेशखाली की पीड़िताओं से मुलाकात भी की। गरीमत है कि संदेशखाली की पीड़िताओं की व्यथा सुनने का वक्त प्रधानमंत्री को मिला। अन्यथा हाथरस, कटुआ नाव की पीड़िताएं अपने दर्द और अन्यथा को भुगतते हुए चली गईं।

चुनावी बांड विवरण पर समय सीमा बढ़ाने की याचिका अनुचित

पी.सुधीर

सरकार ने फैसले के कार्यान्वयन को कमज़ोर करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के माध्यम से कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अप्रैल 2019 से खरीदे गये चुनावी बांड के सभी विवरण सार्वजनिक किये जाने चाहिए, जिसमें खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और बांड का मूल्य शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड योजना को असवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। यह आश्र्य की बात नहीं है कि मोदी सरकार को यह फैसला अरुचिकर लगा, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने के लिए बनाई गई थी।

सरकार ने फैसले के कार्यान्वयन को

कमजोर करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के माध्यम से कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अप्रैल 2019 से खरीदे गये चुनावी बांड के सभी विवरण सार्वजनिक किये जाने चाहिए, जिसमें खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और बांड का मूल्य शामिल है। इसके लिए, भारतीय स्टेट बैंक, जो चुनावी बांड के लेनदेन के लिए एकमात्र एजेंसी थी, को 6 मार्च तक बांड के सभी प्रासारिक विवरण भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उसके बाद चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस सम्बंध में सारी जानकारी सार्वजनिक करनी थी।

सारा जानकारा सापेजानका करना पड़ा। एसबीआई ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनावी बांड लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय मांगा है। इसमें 30 जून तक का समय बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को दिये गये 21 दिनों के बजाय, बैंक अब काम पूरा करने के लिए 116 दिन और चाहता है। दरअसल, इसका अर्थ होगा लोकसभा चुनाव खत्म होने और नवी सरकार बनने

A political cartoon by K. S. Sudarshan. In the foreground, numerous hands are raised, each holding a copy of a booklet titled 'ELECTORAL BOND'. The booklets feature a portrait of Mahatma Gandhi and text in English. In the background, the Indian Parliament building's dome is prominent, with a statue of Mahatma Gandhi standing on top. The scene suggests a widespread distribution or acceptance of electoral bonds as a form of political contribution.

क बाद हा जनता का चुनाव बाड के विवरण के बारे में सूचित किया जायेगा। एसबीआई के अनुरोध को व्यापक आलोचना और उपहास का सम्मान करना पड़ा है। एसबीआई के सभी बैंकिंग परिचालन डिजिटल हो गये हैं। एसबीआई द्वारा दिये गये एक आरटीआई जवाब के अनुसार, चुनावी बांड जारी करने के लिए आईटी प्रणाली के विकास पर कुल 1,50,15,338 रुपये की लागत में से 60,43,005 रुपये खर्च किये गये। यदि चुनावी बांड योजना के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित करने के लिए 60 लाख रुपये से अधिक खर्च किये गये थे, तो यह कैसे हो सकता है कि एसबीआई अब यह दावा करता है कि चुनावी बांड के कुछ रिकॉर्ड एसबीआई के मुंबई मुख्यालय में मैन्युअल रूप से और सीलबंद करव में रखे गये हैं? जब किसी व्यक्ति या इकाई

इसालए, यह बिल्कुल स्पष्ट है। एसबीआई एक घटिया बहाना और गलत कारण लेकर सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की बुद्धिमत्ता का अपमान कर जैसा है। गलत मंशा इस बात से भी स्पष्ट होती है कि एसबीआई ने 6 मार्च से ठीक एक दिन पहले अदालत में अपनी याचिका दायर की, ताकि समय सीधे चूकना एक नियति बन जाये। मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के पास अब तक जारी किये गये और भुनाये गये चुनावी बांड के विवरण के प्रकाशन वरोंके की कोशिश करने का हर कारण है। जैसा कि अदालत ने स्वयं बताया था, यह योजना इस प्रकार तैयार की गयी थी कि प्रतिदान की सुविधा प्रदान की जाए सके। एक बार जब भाजपा को प्राप्त 6,565 करोड़ रुपये के बांड का ब्यौदा पता चल जाये, तो इसका संबंध इस बात से लगाया जा सकता है कि किस कंपनी

लाक्षत्र के एक आर स्तम्भ में दरार



विचार रखते हैं

2017 म गढाचराला का सत्र अदालत ने साईबाबा समेत पांच लोगों को कथित माओवादी संबंधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था। सरकार ने दावा किया था कि 2013 में साईबाबा के घर से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डपकरणों में से कम से कम 247 पेज 'आपराधिक' पाए गए थे, और 2014 में प्रो.जीएन साईबाबा को गिरफ्तार किया गया, तीन साल बाद इस पर मामला चला और अदालत ने नक्सली साहित्य रखने और उसे बांटकर हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में सजा सुनाई। 2022 में हाइकोर्ट ने गढ़चिरौली सत्र अदालत के उस फैसले को पलट दिया था। लेकिन तब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के \$फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले की दोबारा सुनवाई करने की बात कही थी। अब एक बार फिर हाइकोर्ट ने साईबाबा समेत सभी को आशेंपों से मुक्त करने का ही फैसला सुनाया है। इस मामले में इंसाफ नजर तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ फिर वहीं पुराना सवाल चस्पा है कि क्या देर से मिले इस इंसाफ को इंसाफ कहा जा सकता है। न्यायालय की लंबी प्रक्रिया में दो

साल तो इसी बात में गुकि साईबाबा को आरोपों करने का फैसला सही नहीं। इसलिए 2022 में पक्ष में फैसला आने पर बाहर आने के लिए दैनिक इंतजार करना पड़ा। और पहले 9 साल जो जेल में बौद्धिमत्ता की वो अलग। 54 साल के समय व्हीलचेयर से चलते हैं। उनकी प्रतिशत विकलांग हैं, जिसमें भी कोई विशेष शब्दावली के अनुसार कहा जा सकता है। दिव्यांगों के लिए जीवन तौर पर भी नारकीय पीड़ा हुआ है, ऐसे में समझा जाना है कि जेल में 11 वर्षों साईबाबा ने किन बातों साथ बिताए होंगे। जेल में बिगड़ते स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाने वाले परिजनों ने कई बार चिंताओं की, सवाल उठाए, लेकिन अदालत को, न सरकार चिंताओं के बारे में सोचने की फुर्सत मिली। वरिष्ठ वकील जयसिंह ने बिल्कुल सही उठाए हैं कि 'साईबाबा विदेशी गए हैं, लेकिन कितना बाद?' उनके स्वास्थ्य का नुकसान हुआ उसे लौटाएगा? कोट? शर्म कितने और लोगों को जमाने लिए इंतजार करना होगा की आजादी को जिस तरह किया गया, उस नुकसान कीमत कौन चुकाएगा? यह सवाल हैं, जिन पर न्यायिक को सोचना चाहिए। लेकिन

जर गए से मुक्त था या अपने दूर उन्हें भी साल एवं उससे गुजारे पाईबाबा और 99 नहें श्री नाई गई दिव्यांग देश में सामान्य से भरा ग करता साल रहने के इनके उनके उनके जाहिर केन न को इन घने की तड़िदा सबाल बरी कर ने समय को जो कौन करिए। गानत के ? लोगों ह खत्म गान की ये मंथीर पालिका न जब

न्यायपालिका में सियासत अपने असर दिखाने लगे तो क्या इसवालों पर ईमानदारी से विचार होगा, यह एक बड़ी चिंता है। दौर शायद बीत गया है जब न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाएँ ऐसे किसी भी पद को स्वीकार नहीं करते थे, जिससे उन्वें सेवाकाल के दैरान लिए गए फैसलों पर उंगली उठे। अब ऐसे आलोचनाओं से बेपरवाह होकर किसी राजनैतिक दल का हिस्सा बनने से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। जस्टिस रंजन गोगो राज्यसभा के सदस्य बन गए और अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देकर जस्टिस अधिजीत गगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने का एलान किया है। भाजपा के हिंदुत्व राष्ट्रवाद, उसकी कार्यशैली, ये जिस भी वजह से प्रभावित होकर जस्टिस गगोपाध्याय ने राजनीति में जाने का फैसला लिया है। इससे यह संदेह तो उपजेगा है कि न्यायाधीश की आसंदी पर बैठकर उन्होंने जो फैसले राज्य सरकार से जुड़े मामलों में लिये होंगे, उनमें कितनी निष्पक्षता रहेगी। इस देश के सबसे साधारण और गरीब लोगों के लिए उम्मीदों का सबसे बड़ा ठिकाना अदालत ही हुआ करती है, जहां वे इंसाप के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फैसलों पर दल विशेष विचारधारा का प्रभाव या देर रक्खि ए गए न्याय के कारण लोकतंत्र का यह अहम स्तंभ भरकर रहा है।

माहिला सशक्तीकरण पर बेईमान रवैया

बनने के लिए तैयार हो चुका है। सरकारी, गैर-सरकारी संस्थानों में महिलाओं का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम किए होंगे। पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होंगे, जिनमें भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिए जाने की महान परंपरा की बातें होंगी। 21वीं सदी में देश में सेना, विज्ञान, शिक्षा, खेल-कूट, कारोबार, कला-संस्कृति हर क्षेत्र में महिलाओं ने कितनी उन्नति की है, इसके उदाहरण पेश किए जाएंगे। महिला राष्ट्रपति से लेकर विभिन्न किस्म के उच्च पदों पर बैठी महिलाओं की जीवनगाथाएं प्रस्तुत होंगी। हर साल यही सब होता आया है और आगे भी होता रहेगा। स्त्री शक्ति को रेखांकित करते ऐसे आयोजनों में पीड़ित, शोषित और वर्चित महिलाओं की बातें बढ़े सुविधाजनक तरीके से किनारे कर दी जाती हैं। मौजूदा सरकार का भी यही तरीका है। अब 2014 वाला दौर नहीं रहा, जब निर्भया कांड के बाद सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने के लिए जनता अगर सड़कों पर उत्तर आई तो तत्कालीन सरकार ने ऐसा करने से जनता को नहीं रोका, न ही इस मामले को दबाने की कोशिश की या इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा कि उनके कार्यकाल में एक जघन्य अपराध घटित हुआ है। बल्कि तब कांग्रेस सरकार ने निर्भया के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाई, पीड़ितों की मौत के बाद उसके परिवार को राहुल गांधी ने सहारा दिया, उनके भाई को पायलट बनाने में मदद की, लेकिन कभी इस का कोई प्रचार नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बरसों-बरस मनाने और लैंगिक समानता का ढोल पीटने के बावजूद यह एक कड़वी हकीकत है कि महिलाओं के लिए बराबरी और सम्मान की सोच समाज में अब तक व्याप्त नहीं हो पाई है। किस्म-किस्म के भेदभाव और अत्याचार महिलाओं पर होते रहे हैं और इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका व्यापक संबंध समाज की मानसिकता से जुड़ा है। सरकारें अपने फैसलों और नीतियों से इस मानसिकता को सुधारने का काम अवश्य कर सकती हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण जैसे विस्तृत विषय को राजनीति से दूर रख सकती हैं। खेद है कि मौजूदा केंद्र सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे एकाध नारे और दो-चार योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री नारी सशक्तीकरण का श्रेय लेना चाहते हैं। नये संसद भवन में महिला आरक्षण पर विधेयक पारित करवा कर उन्होंने इतिहास रचने का दावा भी किया, हालांकि उनके दावों की हकीकत कई बार जनता देख चुकी है। महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर उनका दुर्भाग्यापन भी अब सामने आ चुका है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी प.बंगल में थे, जहां हाल ही में उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख पर लगा है। शाहजहां शेख फिलहाल कानून की गिरफ्त में है। प.बंगल में भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में भाजपा की नारी शक्ति अभिनंदन रैली की और इसमें कहा कि संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन टीएमसी सरकार अपराधी को बचाने पर तुली हुई है। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके दस साल के शासनकाल में महिलाएं कितनी मजबूत हुई हैं। श्री मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। गनीमत है कि संदेशखाली की पीड़िताओं की व्यथा सुनने का वक्त प्रधानमंत्री को मिला। अन्यथा हाथरस, कतुआ, उन्नाव की पीड़िताएं अपने दर्द और अन्याय को भुगतते हुए चली गईं। मणिपुर की महिलाओं के दर्द का जिक्र तो प्रधानमंत्री करना ही नहीं चाहते।

विदेश संदेश

मैक्सिको की सीमा पर अमेरिका
का नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर
दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत

वाशिंगटन

टेक्सास में अमेरिका-मैक्सिको की सीमा के पास नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौजूद कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में एक नेशनल गार्ड सैन और तीन बॉर्डर पैट्रोल एंजेंट मौजूद थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह हादसा साथ में हुआ था।

मैक्सिको का टार्टल के सदस्यों ने ड्रोन से देखा हादसा

टेक्सास के नागरिक सुरक्षा विभाग के दबिश क्षेत्र के निदेशक विक्टर एस्कॉलोन ने बताया कि बॉर्डर पैट्रोल के साथ काम करने वाले सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। टेक्सास नागरिक सुरक्षा विभाग ने हेलीकॉप्टर के अंपरेशन लोन स्टार में शामिल नहीं होने की पुष्टि की है। बॉर्डर पैट्रोल के सूत्रों ने बताया कि हादसे के दौरान मैक्सिको का टार्टल के सदस्यों पर चाहरा तोड़ा था। इसके बाद जारी करने के बाद हांसते हुए देखा गया। इसी साल 27 फरवरी को नेशनल गार्ड ने अपने एक बलाव में बताया कि उनके लेप्टिनेंट जनरल जॉन ए. जेनसेन ने हाल ही में दो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा की नियतों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एस्पी बैनिंग नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर इकाइयों की विमान सुरक्षा को रोकने का आदेश दिया है। इससे पहले 23 फरवरी को मिसिसिपी में एक बलाव के दौरान एक सन्धै हेलीकॉप्टर जंगली इकाइयों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में दो सैनिकों की मौत हो गई थी। बूटा में प्रशिक्षण के दौरान ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो पायलट घायल हो गए थे।

यात्री ने गुड-लक के लिए हवाई जहाज के इंजन में फेंका सिक्का, चार घंटे के लिए रोकनी पड़ी उड़ान

वीजिंग

सान्धा से बीजिंग के लिए चाइना सर्दन एयरलाइंस की उड़ान छह मार्च को यात्रियों के लिए नियाशानक साबित हुई। दरअसल, चाइना सर्दन एयरलाइंस सुबह के 10 बजे उड़ान भरने वाला था, लेकिन एक असामान्य घटना के कारण यात्रियों को चार घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एक यात्री ने हवाई जहाज के इंजन में ही सिक्का फेंक दिया था।

हवाई जहाज के इंजन में यात्री ने फेंका सिक्का चीनी मीडिया के अनुसार, लंबे इंतजार के बाद दर्दी की बजह सामने आई। इस घटना से जुड़े एक वीडियो के अनुसार, हवाई जहाज के इंजन में सिक्का फेंकने वाले यात्री से प्लाइट अटेंडेंट को पृथुताछ करते हुए देखा गया। यात्री की इस अंधविश्वास के कारण अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय समयनुसार प्लाइट दोपहर के 2:16 बजे तक रवाना नहीं हो पाई।

हालांकि, जहाज के दौरान सुरक्षाकार्यों ने सिक्का ढूँढ़ा निकाला। उन्होंने सिक्कों की संख्या का खलासा नहीं किया। इस घटना पर चाइना सर्दन एयरलाइंस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना को असम्भव व्यवहार बताया है। एयरलाइन ने हवाई जहाजों पर बस्तुएं फेंकने के मामलों में कहा कि यह विमान सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसके लिए आरोपियों को सजा दी जाएगी।

तीन साल पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

चीन में 2021 में इसी तरह एक घटना के कारण उड़ान को रद्द कर दिया गया था। इस उड़ान में कार्यवाही के बाद दौरान जारी करने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा है। इसके लिए आरोपियों को सजा दी जाएगी।

तीन साल पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

चीन में 2021 में इसी तरह एक घटना के कारण उड़ान को रद्द कर दिया गया था। इस उड़ान में कार्यवाही के बाद दौरान जारी करने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा है। इसके लिए आरोपियों को सजा दी जाएगी।

तीन साल पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

चीन में 2021 में इसी तरह एक घटना के कारण उड़ान को रद्द कर दिया गया था। इस उड़ान में कार्यवाही के बाद दौरान जारी करने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा है। इसके लिए आरोपियों को सजा दी जाएगी।

एयरट्रॉप करते वक्त नहीं खुल पाए पैराशूट, नीचे खड़े लोगों के सिर पर गिरा पार्सल, पांच मौत

गाजा

इस्टाइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच, गाजा में एक हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। दरअसल, शुक्रवार को गाजा में मानवीय सहायता एयरट्रॉप की गई। इस दौरान कुछ पैराशूट नहीं खुल पाए और एक पैलेट लोगों पर जा गिरा, जो सहायता की आस में नीचे खड़े थे। पांच लोगों की मौत के अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। गाजा के स्थानीय प्रशासन ने इसकी निवारी की है। गाजा ने एक बयान जारी कर कहा कि हानि पहले ही तेजावनी दी थी कि गाजा भी में एयरट्रॉप सुविधा नामिकों के जीवन के लिए प्रतिक्रिया दी गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल में ही लिया था फैसला

बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में गाजा में मानवीय सहायता के खतरनाक है। एयरट्रॉप सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। एयरट्रॉप सुविधा शुरू करने की घोषणा व्हाइट हाउस से ऑवल ऑफिस में इंटली के प्रधानमंत्री जियोनिया बेलोनी के साथ बैठक के दौरान हुई थी। मीडियों ने अमेरिकी अनुसार, एयरट्रॉप का उद्देश्य गाजा में फलकनीलों लोगों को आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करना है। गाजा में भोजन, दवा और पानी जैसी आवश्यक आपूर्ति के प्रवेश को सुनिश्चित करना था।

हमास और इस्टाइल के बीच युद्ध का यह है कारण

हमास ने कहा कि ये व्यक्तिगत में अल-अक्सा मस्जिद को इस्टाइल की तरफ से अपावित करने का बदला है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास के बीच युद्ध का यह है कारण

हमास ने कहा कि ये व्यक्तिगत में अल-अक्सा मस्जिद को इस्टाइल की तरफ से अपावित करने का बदला है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड भेंट इसे अपावित किया था। इस्टाइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बैनरों के बाद रही है और अंतिक्रमण कर रही है।

हमास ने कहा कि इस्टाइ